

“ किसी मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, न कि उसकी सम्पत्ति ”

अरस्तु ...

भारत टाइम्स

www.bharattimenews.com

सत्यमेव परं श्रुतम्

Bharattimesnews01@gmail.com

जेरण में दुदेश्वर महादेव में...



वर्ष- 2

अंक-122

दिल्ली, शुक्रवार 14 जून 2024

पेज-8

ई-पेपर नई दिल्ली से प्रसारित

न्यूज ब्रीफ

मनोज जरांगे ने स्थगित की भूख-हड़ताल



मुंबई। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा की है। बता दें कि मनोज जरांगे पिछले छह दिनों से हड़ताल पर थे। वे लगातार मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जरांगे चाहते हैं कि मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत आरक्षण दिया जाए। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के जालना जिले में अपने पतुक् गांव अंतर्वाली सराटी में शनिवार को विरोध प्रदर्शन शुरू किया और चेतावनी दी थी कि अगर सरकार इस मुद्दे का तुरंत समाधान नहीं करती है तो वह नरसों के माध्यम से शरीर में तरल पदार्थ लेना भी बंद कर देंगे।

जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोले गए



भुवनेश्वर। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार गुरुवार को मंगला आरती के दौरान श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस दौरान राज्य के नए सीएम मोहन चरण माझी के साथ उनका मंत्रिमंडल, पुरी के सांसद सखित पात्रा और बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी मौजूद रहे। सभी ने द्वार खुलाने के बाद मंदिर की परिक्रमा की। कोरोना काल में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार ने मंदिर के अष्ट द्वार (उत्तर द्वार), व्याघ्र द्वार (पश्चिम द्वार) और हरित द्वार (दक्षिण द्वार) बंद करने के आदेश दिए थे। सिर्फ सिंह द्वार ही खुला था, जिससे श्रद्धालु मंदिर में आते-जाते थे। इस कारण मंदिर में भारी भीड़ और लंबी कतारें लगी रहती थीं। श्रद्धालु लंबे वक्त से सभी द्वार खोलने की मांग कर रहे थे।

18 को जारी होगी किसान सम्मान की किस्त



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9.3 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे। इसमें 20 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले 28 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी। इसमें 21 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को ट्रांसफर किए गए थे। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तों में 6000 रुपए ट्रांसफर करती है।

एनटीए ने 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स किए रद्द, दोबारा देना होगा एग्जाम... 23 जून को परीक्षा होगी, 30 जून तक मिलेगा रिजल्ट

नीट छात्रों की बड़ी जीत! केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले- पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं



भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार याचिकाकर्ता को कहा कि आपकी बात एनटीए ने मान ली है। वो ग्रेस मार्क को हटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी। एनटी ने कहा 23 जून को दोबारा परीक्षा (1563) होगी उसके बाद काउंसिलिंग होगी। एनटीए ने कहा कि तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं है। एनटीए ने कहा कि परीणाम 30 जून से पहले आ सकता है। नीट परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं, जिसमें से ग्रेस मार्क्स, री-एग्जाम और परीक्षा केंसिल वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। नीट परीक्षा को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि काउंसिलिंग नहीं रोकी जाएगी। वहीं, एनटीए ने कहा है कि वे हाईकोर्ट में दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कराने के लिए पिटीशन फाइल करेंगे। किसी छात्र का नुकसान नहीं होने देंगे- उधर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप को सिर से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। एनटीए में भ्रष्टाचार नहीं मिला है।

दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नीट की परीक्षा में 24 लाख छात्र बैठे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और यह सुनवाई 1563 छात्रों के संबंध में है। सरकार कोर्ट में जवाब देने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पर सरकार ने शैक्षिक जगत से जुड़े लोगों की एक समिति बनाई जा रही है। इस समिति की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनटीए ने देश में तीन बड़ी परीक्षाएं नीट, जेईई और सीयूईटी सफलतापूर्वक आयोजित कराई हैं। घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं छात्रों और उनके परिजनों को आश्वासन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार और एनटीए सभी प्रभावितों को न्याय दिलाएगी। 24 लाख छात्रों ने सफलतापूर्वक नीट की परीक्षा दी है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। न ही इसका कोई सबूत मिला है। 1563 बच्चों की दोबारा परीक्षा के लिए कोर्ट ने जो तरीका सुझाया है, उसके मुताबिक ही काम होगा और हम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा में दी विकास की सौगात, कहा...

प्रदेश की 212 नदियों के जल का होगा संरक्षण



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को रीवा दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि रीवा से हमारा गहरा नाता है। मेरी ससुराल है। साथ ही संस्कृति को बचाने का माध्यम भी है। मुख्यमंत्री ने यहां जल गंगा संवर्धन अभियान में हिस्सा लिया। मंच से उन्होंने कहा कि चित्रकूट के जंगल में यदि कोई भूल से चला जाए तो भूखे नहीं मर सकता। ऐसी भगवान की कृपा है। आयोजन का उद्देश्य है कि जन-जन में यह भाव पैदा हो कि हमारे जो भी जल स्रोत हैं, उनका संरक्षण किया जाए। सभी पुरानी जल संरचनाओं को संभालने

की जिम्मेवारी हमारी है। रीवा में जो भी पुरानी जल संरचना है, उसके लिए जो भी जरूरत होगी, वो बताएं। सरकार उसे पूरा करेगी। जहां भी नदी किनारे जल संरक्षण की पुरानी संरचनाएं बनी हैं, उन्हें संरक्षित करने का काम सरकार करेगी। प्रदेश की 212 नदियों के जल का संरक्षण का लक्ष्य रखा है। सीएम ने कहा कि गोमाता की चिंता अगर भारत में नहीं करेंगे। मध्यप्रदेश में नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे। इसके लिए हमने प्रत्येक गांव के लिए प्रतिदिन 20 रुपए की जगह 40 रुपए का बजट दिया। सभी विधायकों से आग्रह

70 करोड़ से अधिक राशि के कार्यों का शिलान्यास

मुख्यमंत्री मोहन यादव 70 करोड़ 91 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही 48 करोड़ 2 लाख रुपए के 58 कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के 47 उच्च स्वास्थ्य केन्द्र भवन और 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा 22 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत के 14 निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी होना है, जिसमें दो अनुसूचित जाति छात्रावास, 8 उच्च स्वास्थ्य केन्द्र भवन और 2 पुलों के निर्माण कार्य शामिल हैं।

करेंगे कि प्रत्येक विधानसभा में ऐसी गोशाला खोले, जिसमें दिव्यांग गांवों को संरक्षित किया जा सके। जिस गांव को रखने में किसान को परेशानी हो, वैसी गांवों को इन गोशालाओं में स्थान देकर सेवा का प्रकल्प विकसित किया जाए। मंच पर मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिश गौतम सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह मौजूद हैं। इसके बाद सीएम लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर बावड़ी की साफ-सफाई और बिडिया नदी के घाट के साफ-सफाई में भी शामिल होंगे। अंत में मुख्यमंत्री मंदिर परिसर में जनसभा करेंगे।

26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की



नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव संपन्ना होने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। सरकार का गठन होने के साथ ही मंत्रियों को उनके मंत्रालय भी सौंप दिए गए हैं। इस सभ्य की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 18वें लोकसभा का स्पीकर कौन होगा? इस प्रश्न का उत्तर 26 जून को मिल जाएगा। दरअसल 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। उधर इस तरह की भी खबरें हैं कि राजस्थान की कोटा-बूंदी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले ओम बिड़ला को एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर की कमान सौंपी जा सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन डी पुरुदेश्वरी के नाम पर भी चर्चा चल रही है।

हिमाचल का दिल्ली को पानी देने से इनकार एक दिन पहले हामी भरी थी

नई दिल्ली। दिल्ली में जल संकट को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश ने कोर्ट को बताया कि हमारे पास दिल्ली को देने के लिए 136 ब्यूसेक पानी नहीं है। जबकि एक दिन पहले हिमाचल ने कहा था कि हमारी तरफ से पानी छोड़ा गया है। हरियाणा की तरफ से पानी सप्लाई किया जाना बाकी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना के पानी का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। हमारे पास दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जल-बंटवारे के फॉर्मूले पर फैसला लेने की टैक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पानी देने का फैसला अपर रिवर यमुना बोर्ड पर छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि यमुना रिवर बोर्ड ने पहले ही दिल्ली को मानवीय आधार पर पानी की आपूर्ति के लिए आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है।

शहीद कबीर दास का छिंदवाड़ा में अंतिम संस्कार

सीआरपीएफ जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, कटुआ आतंकी हमले में घायल हुए थे छिंदवाड़ा। जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले में जवान शहीद कबीर दास उईके का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीआरपीएफ जवानों ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद शहीद कबीर को उनके घर के पीछे खेत में दफनाया गया। यहां स्मारक बनाया जाएगा। इससे पहले शहीद की पार्थिव देह पहले हवाई मार्ग से गुरुवार सुबह नागपुर लाई गई। यहां से सड़क मार्ग से पैतृक गांव पुलपुलडोह (मरजातपुर) ले जाया गया। उनकी अंतिम यात्रा के दर्शन करने के लिए लोग घरों की छतों पर चढ़ गए। अंतिम संस्कार के समय सीआरपीएफ के आईजी सुखवीर सिंह सोढी और डीआईजी नीतू सिंह भी मौजूद रहें। वहीं, छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और एसपी मनीष खत्री भी मौजूद थे। मंगलवार रात 8 बजे जम्मू-कश्मीर के कटुआ जिले के हीरानगर स्थित सेदा सुखल गांव में आतंकी हमला हुआ था।

जम्मू-कश्मीर के स्कूलों में राष्ट्रगान को शामिल करने के निर्देश

घाटी के स्कूलों में गूंजेगा जन गण मन...

नई दिल्ली। शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के हर स्कूलों में सुबह की असेंबली की शुरुआत करने और इसमें अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान को शामिल करने का निर्देश दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक परिपत्र के माध्यम से सभी स्कूलों को केंद्र शासित प्रदेश में सुबह की सभा को एक समान बनाने का निर्देश दिया। बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा गया, मानक प्रोटोकॉल के अनुसार सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से होनी चाहिए। विभाग ने कहा कि मॉनिंग असेंबली छात्रों के बीच एकता और अनुशासन को भावना पैदा करने में एक अमूल्य

हालांकि, यह देखा गया है कि इस तरह के एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान/परंपरा को जेके यूटी के विभिन्न स्कूलों में समान रूप से नहीं चलाया जा रहा है। सर्कुलर में स्कूलों को पालन करने के लिए 16 कदम सुझाए गए थे। विभाग ने अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित करने, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और नशीली दवाओं के खतरे को दूर करने और नशीली दवाओं के खतरे को दूर करने के लिए स्कूलों को सुबह की सभाओं में शामिल करने के कुछ कदमों के रूप में सुझाव दिया। पीएम को दी गई जम्मू-कश्मीर के हाल की जानकारी उधर, प्रधानमंत्री ने एनएएसए और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मू-कश्मीर की स्थिति की समीक्षा की। पीएम को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालात की पूरी जानकारी दी गई और उन्हें आतंकवाद विरोधी प्रयासों से अलग कराया गया। पीएम ने उनसे हमारी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने को कहा। पीएम ने गृहमंत्री अमित शाह से बात की और सुरक्षा बलों को तैनाती और आतंक विरोधी अभियानों पर चर्चा की। एलजी मनोज सिन्हा से भी पीएम मोदी ने की बात पीएम ने जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी बात की और जम्मू-कश्मीर के हालात का जायजा लिया। पीएम को स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई।

लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखेगी भाजपा

पीएम मोदी विदेश से लौटने के बाद करेंगे फैसला

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया में आ रही खबरों को खारिज करते हुए बताया कि किसी भी सहयोगी दल की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर कोई मांग नहीं आई है।



नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखने जा रही है। यानी 18वें लोकसभा में भी भाजपा का ही कोई सांसद लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया में आ रही खबरों को खारिज करते हुए बताया कि किसी भी सहयोगी दल की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर कोई मांग नहीं आई है। भाजपा जल्द ही पहले पार्टी के स्तर पर इस पर विचार करेंगी और पार्टी द्वारा नाम पर

फैसला किए जाने के बाद एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भी विचार-विमर्श कर उस नाम पर सर्वसम्मति बनाई जाएगी। मोदी के पहले कार्यकाल में महाजन तो दूसरे में बिरला थे अध्यक्ष मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मध्य प्रदेश की इंदौर से भाजपा की लोकसभा सांसद सुमित्रा महाजन को और दूसरे कार्यकाल में राजस्थान के कोटा से भाजपा सांसद ओम बिरला को

लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन इस बार के तीसरे कार्यकाल में भाजपा के पास 2014 और 2019 की तरह लोकसभा में बहुमत नहीं है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि टीडीपी लोकसभा के अध्यक्ष का पद मांग रही है। जेडीयू से भी लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने की बात सामने आई लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने इन खबरों को महज अटकलें बताते हुए खारिज कर दिया।

24 जून से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र

24 जून से शुरू होने जा रहे 18 वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान भाजपा अपनी पार्टी के किसी सांसद के नाम को लेकर विपक्षी दलों से भी संपर्क साधेगी, ताकि सदन में सर्वसम्मति से लोकसभा के नए अध्यक्ष का चयन हो सके। अगर सरकार के प्रस्ताव को विपक्षी दल स्वीकार कर लेते हैं, तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर विपक्ष अपनी तरफ से भी उम्मीदवार खड़ा करता है, तो 26 जून को लोकसभा में नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान हो सकता है। दोनों ही सूरत में लोकसभा के नए अध्यक्ष 26 जून को कार्यभार संभाल लेंगे।

Regd. 202045

भारतीय पत्रकार समिति

पत्रकारों के हक में - पत्रकारिता के हित में

तेजी से उभरता भारत का सबसे बड़ा पत्रकारों का संगठन

पत्रकारिता से जुड़े व्यक्ति सदस्य बनने के लिए अपना बायोडाटा आईडी कार्ड सहित ईमेल करें

राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू

Email: indianjournalistcommittee@gmail.com

मुख्यमंत्री का निर्णय, खुर्जा और बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण को मिलाकर गठित होगा नया प्राधिकरण

खुर्जा, बुलन्दशहर और मुरादाबाद के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री ने किया महायोजना पर विचार

सभी नगरों में इनर रिंग रोड का विकास करना आवश्यक, तैयार करें कार्ययोजना: मुख्यमंत्री

- सीमा विस्तार में शामिल नए गांवों को महायोजना में आबादी के रूप में ही दर्ज करें, ग्रीन बेल्ट के रूप में नहीं: मुख्यमंत्री
- नदियों, पोखरों व अन्य जलाशयों पर अतिक्रमण स्वीकार नहीं, लखनऊ की कुकरैल नदी की तर्ज पर करें कार्यवाही: मुख्यमंत्री
- महायोजना में मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एजुकेशन सिटी, कन्वेंशन सेंटर आदि के लिए स्पष्ट क्षेत्र चिह्नित हों
- जनसमस्याओं के निस्तारण में तेजी लाएं, नक्शा पास कराने जैसी सामान्य कार्यों में अनावश्यक विलम्ब न हो: मुख्यमंत्री

यह मिले दिशा-निर्देश



- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष आज एक उच्च स्तरीय बैठक में खुर्जा, बुलन्दशहर और मुरादाबाद विकास प्राधिकरणों की जीआईएस आधारित महायोजना-2031 के प्रस्तुतिकरण के अवलोकन किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा निर्देश...
- खुर्जा और बुलन्दशहर दो अलग-अलग विकास प्राधिकरण के रूप में गठित हों, जबकि दोनों ही विकास प्राधिकरणों में आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समरूपता है। पूरा क्षेत्र एक ही जनपद बुलन्दशहर के अंतर्गत आता है। विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाओं को बनाने और उनके सुगम क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि दोनों प्राधिकरणों को मिलाकर एक बड़े विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी कराएं।
- खुर्जा का सिरैमिक उद्योग देश-विदेश में विशेष पहचान रखता है। वर्ष 2021 में 23 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य के सिरैमिक उत्पाद निर्यात किए गए। इस सेक्टर में अभी बहुत संभावना है। आवश्यकता है कि इससे जुड़े उद्यमियों, शिल्पियों की अपेक्षाओं के अनुसार सुविधाओं का विस्तार किया जाए। उन्हें मार्केट उपलब्ध कराएं। सिरैमिक हट का निर्माण कराएं।
- जेदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुर्जा के समीप ही है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का लाभ भी खुर्जा को मिल रहा है। यह विशेष स्थिति खुर्जा को मध्य में निर्यात का हब बनने में बड़ी भूमिका निभाएगा। पॉर्टरी उद्योग के उद्यमियों के लिए एक नए इंडस्ट्रियल एरिया का विकास भी किया जाना चाहिए।
- रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की नीति के साथ सभी नगरों में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ठोस कार्ययोजना लेनी चाहिए। इसे महायोजना में स्थान दें। एसटीपी/सीटीपी का निर्माण कराएं। लैंडफिल साइट पहले से चिह्नित हो। नई तकनीक को अपनाएं।
- मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे अतिक्रमण की स्थिति है। ऐसी ही स्थिति काशी, सहरनपुर आदि जनपदों में भी दे रखी जा सकती है। अभी लखनऊ में कुकरैल नदी के पुनर्जीवन की कार्यवाही हो रही है। अदेध बसावट को हटा कर उन्हें अन्यत्र पुनर्वासित कराया गया है। इसी प्रकार, अन्य जिलों में भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यवाही की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित कराएँ कि नदी बेसिन में कोई बसावट न हो। पुराने तालाबों/पोखरों व अन्य जलाशयों को संरक्षित करें। अतिक्रमण हो तो तत्काल हटाएं।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि हर नगर की महायोजना में हरित क्षेत्र के लिए आरक्षित हो। जहां कहीं भी ग्रीन बेल्ट है, वहां किसी भी दशा में नई कॉलोनी न बसने पाए।
- सीमा विस्तार में शामिल नए गांवों को महायोजना में आबादी के रूप में ही दर्ज किया जाए। किसी भी दशा में इसे ग्रीन बेल्ट न कहा जाए। इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर आवश्यक कार्यवाही आगे बढ़ाई जानी चाहिए।
- सभी नगरों में इनर रिंग रोड का विकास करना होगा। इस इनर रिंग रोड के बगल में विभिन्न लिंक रोड पर सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। नगर के अंदर के कंजेशन को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि रिंग रोड के किनारे पर अलग-अलग व्यवसायिक गतिविधियों का विकास करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कहीं स्पोर्ट्स सिटी, मेडि सिटी, नॉलेज सिटी, नेचर पार्क, आयुष पार्क आदि का विकास किया जाना चाहिए।
- महायोजना में शामिल नई कॉलोनी के विकास पर ध्यान दें। वहां सड़क, सीवर, बिजली, पानी जैसी सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो। महायोजना को अंतिम रूप देते समय यह ध्यान रखें कि यदि कोई धार्मिक स्थान है तो उसे उसी रूप में दर्ज करें।
- नगरों में यातायात प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है। हमें इसके लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। सड़कों के चौड़ाकरण करते समय ड्रेनेज और यूटिलिटी डाक्ट की व्यवस्था बेहतर ढंग से की जाए।
- जनसमस्याओं के निस्तारण में तेजी लाएं। नक्शा पास कराने जैसे सामान्य कार्यों में अनावश्यक विलम्ब न हो। प्राधिकरणों में अच्छे टाउन प्लानर की तैनाती करें। अपना दायरा बढ़ाएँ। आय के नए स्रोत सृजित करें।



